

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1431

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

“वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” के अंतर्गत नए गांवों को शामिल करना

1431. डॉ. आन्नद कुमार गोंडः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहराइच जिले के मिहीपुरवा और नवाबगंज विकास खंडों में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित 34 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चरण 2 के अंतर्गत चुना गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त गांवों में विकास कार्यों हेतु तैयार की गई विशेष कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए बजट आवंटित और जारी किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बहराइच के बाकी गांवों, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और दुर्गम ग्रामीण इलाके हैं और विकास की मुख्यधारा से वंचित हैं, को अगले चरण में शामिल करने का है या जल्द ही शामिल किए जाने की संभावना है जिन्हें अभी तक इस योजना में शामिल नहीं किया गया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क से घ): केंद्र सरकार ने 6839 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) को अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं (आईएलबी) (उत्तरी सीमाओं को छोड़कर, जो वीवीपी-I के अंतर्गत सम्मिलित हैं) से सटे ब्लॉकों के चुनिंदा गांव, जिसमें बहराइच जिले के मिहीपुरवा और नवाबगंज विकास खंडों में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित 33 सीमावर्ती गांव सम्मिलित हैं, को स्वीकृति दी है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित गांवों के विकास के हेतु हस्तक्षेप के चिन्हित फोकस क्षेत्र है (i) आजीविका सृजन, (ii) सड़क सम्पर्क, (iii) उर्जाकरण, (iv) स्वास्थ्य सुविधाओं सहित ग्रामीण अवसंरचना (v) वित्तीय समावेशन, (vi) युवाओं का सशक्तिकरण और कौशल विकास, (vii) आजीविका के अवसरों के प्रबंधन और

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1431, दिनांक 09.12.2025**

कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई परिसंम्पतियों के रखरखाव के लिए सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और फूड प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन का विकास, (viii) पर्यटन , संस्कृति एवं आउटरीच कार्यकलाप को बढ़ावा देना, (ix) शिक्षा अवसंरचना एवं (x) टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क।

\*\*\*